भारतीय मजदूर संघ

बिहार प्रदेश

महामंत्री का प्रतिवेदन

19वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन

26 एवं 27 अप्रैल, 2003

स्थान

वीणापाणी क्लब, बंगाली टोला
न्यू बलभद्रपुर, लहेरियासराय
दरभंगा

महामंत्री का प्रतिवेदन

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, कार्य समिति के सम्मानित सदस्यगण, प्रतिनिधि बन्धुओं एवं बहनों।

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश के 19वें अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

हमारा यह अधिवेशन पूर्व बिहार के विभाजन के पश्चात् नव-बिहार की दृष्टि से प्रथमतया एवं अनेक प्रकार से विरलता तथा समग्र कठिनाईयों के बीच सम्पन्न हो रहा है; आप सभी भली भांति अवगत हैं। यह स्थान जहाँ हम अधिवेशन सम्पन्न करने में जुटे हैं मैथिली के महान् कवि मैथिलकोकिल विद्यापति के जन्म एवं कर्मस्थली के रूप में अत्यंत गौरवशाली रहा है। पिछली बार हम दिसम्बर 24 एवं 25, 2000 को बेगूसराय में मिले थे। तब से अबतक के इस कालखण्ड का एक अति संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रद्धांजलि : विगत अधिवेशन तथा वर्त्तमान अधिवेशन के अन्तराल जो हमारा साथ छोड़ गये उन महान् हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भारतीय मजदूर संघ के समर्पित कार्यकर्त्ताओं का इस 19वें अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित हम सभी प्रतिनिधि नतमस्तक होकर उन हुतात्माओं के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनमें से कुछेक पवित्रात्माओं के नाम स्मरणीय हैं:—यथा, उपराष्ट्रपति–कृष्णकान्त, लोकसभा अध्यक्ष–बालयोगी, प्रसिद्ध न्यायविद–नानापालकीवाला, सांसद–जगदम्बी प्रसाद यादव एवं माधवराव सिंधिया, वरिष्ठ भाजपा नेता–हरेन भाई पांडया, सांसद नरेन्द्र मोहन, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, लेखिका–गौरापंत शिवानी, क्रान्तिकारी बटुकेश्वर दत्त की धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि दत्ता, वरिष्ठ प्रचारक–रा० स्वयं सेवक संघ श्रीधर प्रसाद, श्रीकृष्णचन्द्र गाँधी, व्यवस्था प्रमुख रा० स्वयं सेवक संघ, दक्षिण बिहार–विजय कुमार सिंह, विभाग कार्यवाह–मेवाराम, धनबाद, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ एवं प्रमुख कार्यकर्त्ता–आवाजी पुरानिक, रासबिहारी मित्र, चरण सिंह, कोमल सिंह परिहार एवं अम्बिका प्रसाद सिंह, वारीडीह कोलियरी दुर्घटना, गुजरात तुफान त्रासदी एवं हाल के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में अग्निकांड में मृत रामभक्त कारसेवकों तथा नदीमर्ग में आतंकवादियों द्वारा 24 लोगों की हत्या आदि से कालकवलित असंख्य आत्माओं के प्रति भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य—सम्पूर्ण विश्व आज अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से त्रस्त है। भारत, अमेरिका, इजराईल, रूस आदि प्रमुख देश भी आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। वहीं श्रीलंका, वर्मा, बंगलादेश, नेपाल, इन्डोनेशिया तथा कुछ अफ्रीकी देश भी आन्तरिक उग्रवाद से ग्रस्त हैं। भारत का पूर्वांचल भाग आन्तरिक आतंकवाद झेलने पर मजबूर है, वहीं कश्मीर में पाकिस्तानी सह पर लश्कर तोयबा आदि उग्रवादी गुट तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी युवकों को बहकाकर उन्हें उग्रवादी बनाने का सिलसिला

जारी है। वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान आइ. एस. आई. एजेन्टों के माध्यम से एक प्रकार से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है।

दूसरी तरफ अमेरिका विश्व से आतंकवाद मिटाने के नाम पर दुनिया के देशों पर अपनी दादागिरी के माध्यम से वर्चस्व कायम करने में लगा है। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिका द्वारा इराक पर हमला। आतंकवाद की लड़ाई में अमेरिका द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। वह भारत के हितों की अनदेखी कर पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है।

आर्थिक क्षेत्र में भी डब्ल्यू. टी. ओ. के माध्यम से अमेरिका अपने हितों की रक्षा तथा विकासशील देशों का शोषण कर रहा है। वैश्वीकरण-उदारीकरण की नीतियोंके तहत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व व्यापार संगठन के दबाव के चलते गैट की शर्त्तों को मानने की बाध्यता के फलस्वरूप अनेक देशों में बेरोजगारी बढ़ी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। नई आर्थिक नीति का दुष्परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। दिन-प्रतिदिन कारखाने बंद हो रहे हैं तथा मजदूरों की व्यापक छँटनी हो रही है। लोक उपक्रम निजी हाथों में बेचने का सिलसिला भी जारी है।

देश की नई आर्थिक, औद्योगिक नीति नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने भी इन नीतियों को जारी रखा। वर्तमान वाजपेयी सरकार भी जब से आई है उन पुरानी सरकारों की आर्थिक नीतियों को ही बढ़ावा दे रही है।

भारतीय मजदूर संघ आरंभ से ही इन नई नीतियों का सर्वमान्य विरोध करता रहा है। अतः, ऐसी परिस्थिति में सभी देशभक्त श्रमिकों को एकजुट होकर पूँजीवादी देशों द्वारा आर्थिक आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना होगा।

राष्ट्रीय घटनाक्रम—पोखरण में परमाणु विस्फोट कर भारत सरकार ने आत्मरक्षा के प्रति भारतीय जन-मानस में आत्मविश्वास उत्पन्न किया है वहीं विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इस घटना से भारत विश्व में शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में गौरवान्वित हुआ है।

दूसरी ओर भ्रष्टाचार में राजनेताओं की संलग्नता, यू० टी० आई० एवं चारा घोटाला तथा विभिन्न राज्य सरकारों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता, लूट, बलात्कार, अपहरण ने आज उद्योग का रूप ले लिया है, जो एक गंभीर रूप धारण करता जा रहा है।

बंगलादेश नागरिकों का बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अवैध घुसपैठ के कारण आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एम्.सी.सी., पी.डब्ल्यू.जी., रणवीर सेना आदि उग्रवादी संगठनों ने कई जिलों में समानांतर शासन व्यवस्था कायम कर ली है। आये दिन इन संगठनों के उन्मादी प्रतिद्वंद्विता में निर्दोष एवं निरीह लोगों की हत्याएँ हो रही हैं तथा कानून व्यवस्था पंगु बनकर रह गयी है।

उपर्युक्त समस्याओं की ओर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के लिये खतरा बन जायेगा।

तमाम खतरों तथा निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के कारण हमारा मस्तक ऊँचा हुआ है। रक्षा वैज्ञानिकों ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग आदि प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण कर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर गौरव बढ़ाया। सॉफ्टवेयर एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी में भारत विश्व में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। भारतीय प्रतिभाओं ने विश्व के विभिन्न देशों में भी प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। इन परिस्थितियों में कठिन परिश्रम से भारत पुनः गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।

आर्थिक एवं औद्योगिक नीति—वर्तमान आर्थिक नीति, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को केन्द्र सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है। परिणामस्वरूप कारखाने बन्द हो रहे हैं, श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। समूचे सार्वजनिक क्षेत्र चाहे घाटे में हो अथवा लाभ में चलते हों, बड़ी बेचैनी में हैं। देश के समक्ष गंभीर संकट खड़ा है।

ऐसी ही विपरीत परिस्थिति में भारतीय मजदूर संघ एक मजबूत चट्टान की भाँति आर्थिक मोर्चे पर डटा हुआ है। इन आर्थिक नीतियों तथा विश्व व्यापार संगठन के दुष्परिणामों के विरोध में 16 अप्रैल 2001 को भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्ध में "मोड़ो-तोड़ो और छोड़ो" का नारा बुलंद किया गया। यह रैली इतनी विशाल एवं सफल हुई कि मजदूर क्षेत्र में इसे 'न भूतो न भविष्यति" कहा गया। इस रैली के कारण सरकार का, जनता का, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य श्रम संगठनों का ध्यान विश्व व्यापार संगठन से उत्पन्न समस्याओं की तरफ गया, वहीं उनका ध्यान भारतीय मजदूर संघ की ओर भी गया। उस विराट् सभा में मा० दत्तोपंत ठेंगड़ी के भाषण का निष्कर्ष यही था कि गरीब, विकासशील देशों को आर्थिक गुलामी से बचाना हो तथा उनकी संप्रभुता की रक्षा करना हो तो डब्ल्यू. टी. ओ. को मोड़कर उन देशों के हित का निर्णय लेने के लिये बाध्य करना चाहिए। यह संभव न हो तो विश्व व्यापार संगठन को तोड़कर उसे छोड़ देना चाहिए और विकासशील देशों के लिये अलग एक समानान्तर विश्व व्यापार संगठन बनाना चाहिए।

समस्या की गंभीरता को उत्तरोत्तर अध्ययन करते हुए भारतीय मजदूर संघ तथा अन्य समान विचारधारा के राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आन्दोलन को बढ़ाने पर विचार किया गया तथा भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वजागरण मंच आदि के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितम्बर, 2002 से 2 अक्टूबर, 2002 तक संपूर्ण देश के प्रादेशिक राजधानियों में विराट् जुलूस निकाले गये तथा सभाएँ की गयीं जिससे जन जागरण कार्य का और भी विस्तार हुआ।

यही नहीं, अगले चरण में विश्व व्यापार संगठन के दुष्परिणाम तथा सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध में भारतीय मजदूर संघ के विगत सातारा की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने आन्दोलन का अपेक्षित विस्तार करने हेतु देश के जिला केंन्द्रों पर दिनांक 23 जुलाई, 2003 से 9 अगस्त, 2003 तक जन-जागरण, धरना, प्रदर्शन, रैली आदि करने का आह्वान किया है। इस सभा में हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता आगामी कार्यक्रमों को सफल करने का संकल्प करते हैं।

बिहार का औद्योगिक परिदृश्य—बिहार का औद्योगिक परिदृश्य बहुत ही दयनीय एवं भयावह है। हजारों की संख्या में उद्योग बन्द हैं। राज्य सरकार के आँकड़े के अनुसार बिहार में 98 बड़े तथा 30 हजार लघु उद्योग बन्द हैं।

बिहार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण बिहार चीनी निगम, औद्योगिक विकास निगम, लघु उद्योग निगम, फल-सब्जी विकास निगम, बिहार पथ परिवहन निगम आदि 50 से अधिक निगमों का दिवाला निकल गया है। विगत पाँच-छः वर्षों से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में मजदूरों को भूखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। सैकड़ों मजदूरों ने दवा के अभाव में दम तोड़ दिया है। बन्द उद्योगों को चालू करने हेतु तथा उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई कारगर पहल नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप लाखों की संख्या में मजदूर बिहार से पलायन कर रोजगार की तलाश में विभिन्न प्रदेशों में जा रहे हैं। अगर यह स्थिति जारी रही तो बिहार के बचे उद्योगों तथा कृषि कार्य के लिये मजदूर मिलना अत्यंत कठिन हो जायेगा।

दूसरी तरफ बिहार में कानून एवं व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, फलस्वरूप उद्योगपतियों का भी पलायन शुरू हो गया है। कोई भी उद्योगपति चाहे देशी हो या विदेशी, बिहार प्रदेश में पूँजी निवेश करने को तैयार नहीं है।

बिहार के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी राशि का उपयोग राज्य सरकार की अकर्मण्यता, ढुल-मुल नीति तथा रचनात्मक पहल एंवं सुदृढ़ योजनाओं के अभाव में नहीं हो पाता है। राज्य सरकार तथा अन्य राजनैतिक दल के नेताओं में भी बिहार के विकास हेतु पर्याप्त इच्छा शक्ति के अभाव में आज बिहार सबसे पिछड़े प्रदेश की श्रेणी में खड़ा है।

हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थिति में बदलाव लाने के लिये कारगर कदम उठायेगी तथा बिहार की तस्वीर बदलने के लिये सभी राष्ट्रभक्त मजदूरों से यह अपेक्षा करते हैं कि कार्य-संस्कृति में बदलाव, कठिन संघर्ष, मजदूर एकता तथा परिश्रम की पराकाष्ठा द्वारा बिहार को एक विकसित औद्योगिक राज्य के रूप में खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

भारतीय मजदूर संघ—भारतीय मजदूर संघ का कारवाँ लगातार बढ़ते जा रहा है। विशुद्ध श्रमवाद की स्थापना का लक्ष्य लेकर "भारत माता की जय" उद्घोष के साथ भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रगति पथ पर कदम बढ़ाते हुए अन्याय, शोषण और विषमता के खिलाफ संघर्षशील है।

अपनी स्पष्ट नीति सिद्धांतों तथा लगातार संघर्षशीलता के कारण सन् 1989 के आधार पर सदस्यता सत्यापन में सभी श्रम संगठनों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। आज यह सभी केन्द्रीय श्रम समितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नेतृत्वयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुका है तथा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबद्ध न होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।

यह कारवाँ अब श्रमिक जगत में कार्यरत महिला कर्मियों को न्याय तथा सम्मानजनक स्थान दिलाने, बंधुआ तथा ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत असहाय श्रमिकों को मुक्ति दिलाने, असंगठित क्षेत्र के हमारे करोड़ों भाई-बहनों को शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों में अपना मजबूत संगठन खड़ा करने की दिशा में गतिमान हो चुका है।

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश—प्रदेश में कुल 122 रजिस्टर्ड यूनियनें हैं। कुल सदस्य संख्या ..... है। कुल 38 जिलों में से 22 जिलों में जिला समितियाँ, तीन जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक महासंघों की इकाईयाँ कार्यरत हैं, जिनमें से 11 जिलों में जिला संयोजक भी नियुक्त हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या मात्र दो (2) है। पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

दिसम्बर 2000 में बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के पुनर्गठन यानी झारखण्ड प्रदेश बनने के बाद शेष बिहार में इंजीनियरिंग, परिवहन, बीड़ी, आँगनबाड़ी, बैंकिंग, बीमा, विद्युत, डाक, दूरसंचार, रेल, सरकारी कर्मचारी, सुगर, सीमेन्ट,केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं प्रतिरक्षा तथा असंगठित क्षेत्र आदि औद्योगिक केन्द्रों पर ही अपना कार्य सिमट गया। इनमें इंजीनियरिंग, परिवहन, सुगर सीमेंट एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति की भयावहता सर्वजान्य है, शेष में सेवा क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों एवं अपार असंगठित क्षेत्रों में कार्य विस्तार की संभावनाएं हैं। असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से लगभग 20 जिला केन्द्रों पर कार्यकर्त्ता कार्य विस्तार हेतु चिंता कर रहे हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर तथा 17 सूत्री मांगपत्र बनाकर जिला स्तर पर 20.05.2002 से 27.05.2002 तक धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिये गये। असंगठित क्षेत्र में कार्य बढ़ाने हेतु संगठित क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं का भी पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। इस क्षेत्र हेतु नये-नये कार्यकर्त्ताओं की खोजबीन की जा रही है। इस क्षेत्र में कार्य संवर्धन हेतु तहसीलों एवं ग्रामों में संपर्क साधन हेतु डाक, दूरसंचार, विद्युत एवं ग्रामीण बैंकों आदि के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील अपने कार्यकर्त्ताओं को माध्यम बनाने की अपेक्षा है।

वर्ष 1980 एवं 1989 की केन्द्र सरकार की सदस्यता सत्यापन के आधार पर भा० म० सं० बिहार प्रदेश को भी प्रथम स्थान प्राप्त है।

इस अवसर पर संगठित क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ का गौरवपूर्ण स्थान सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में लाखों श्रमिकों के बीच प्रदेशव्यापी कार्य-विस्तार का लक्ष्य लेकर सभी प्रतिनिधि अपने-अपने कार्य में जुट जायँ, यही समय की उत्कट माँग है।

जिला केन्द्र—भारतीय मजदूर संघ के प्रभावी कार्य एवं कार्य-विस्तार की दृष्टि से जिला केन्द्रों को सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अतः सभी जिलों में जिला समितियाँ गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिला में प्रबुद्ध, सक्रिय तथा समर्पित कार्यकर्त्ताओं की सूची बनाने तथा जिला को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने हेतु भी विगत पटना प्रदेश कार्यसमिति में निर्णय लिये गये थे जिसके मुताबिक, प्रदेश द्वारा जिला को रसीदें दी गयी थीं तथा कोष संचालन हेतु बैंक में संयुक्त लेखा खोलने का मार्गदर्शन किया गया था। अपेक्षित सफलता हेतु, सतत् प्रयास की आवश्यकता है। प्रभावी जिला केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष में निश्चित अवधि यानी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सभी संबंधित यूनियनों के सम्मेलन के पश्चात् 30 जून तक जिलों का सम्मेलन-सह-अभ्यास वर्ग करने की आवश्यकता पर भी निर्णय लिया गया था। इन निर्णयों का दृढ़ता से पालन करने से ही जिला केन्द्र सशक्त हो सकते हैं।

महिला विभाग—प्रदेश की आँगनबाड़ी कर्मियों तथा महिला विभाग का संयुक्त सम्मेलन दिनांक 30.06.2002 को पटना जी० पी० ओ० परिसर में संपन्न हुआ था जिसमें महिलाओं में नेतृत्व विकास तथा उनकी समाज कार्य में प्रबल सहभागिता एवं महिलाओं से सम्बन्धित अनेक कटु सत्य युक्त समस्याओं पर श्रीमती चन्द्रमुखी देवी, पूर्व विधायिका एवं संस्कार भारती की कार्यकर्तृ का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लगभग 100 महिलाएँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं।

बिहार श्रम संगठन मंच—यह सुखद है कि बिहार प्रदेश में सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों का एक मंच है जिसके तत्वावधान में सर्वमान्य समस्याओं अथवा अन्यान्य संयुक्त मोर्चा के माध्यम से संयुक्त कार्यक्रम होते हैं। केन्द्रीय आह्वान पर दिनांक 8.7.2001 को पटना में कन्वेंशन तथा 24.7.2001 को पटना में संयुक्त रैली महत्त्वपूर्ण है। मजदूरों के हितों के समान मुद्दों पर श्रम संगठनों की एकता के हम पक्षधर हैं।

कुछ नियमित कार्यक्रम :

1. **स्थापना दिवस**—23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष भारतीय मजदूर संघ की विभिन्न इकाईयों, जिला मुख्यालयों में भारतीय मजदूर संघ का झंडा लगाकर, कार्यकर्त्ताओं को बैज वितरण कर, गोष्ठियाँ/सभाएँ की जाती हैं, तथा भारतीय मजदूर संघ के सिद्धांतों पर चिन्तन मनन करते हैं। यह कार्यक्रम लगभग सभी सक्रिय इकाईयों निश्चित रूप से करती है।

2. **राष्ट्रीय श्रम दिवस**—प्रत्येक वर्ष 17 सितम्बर को हम विश्वकर्मा जयन्ती का आयोजन राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में करते हैं तथा विश्वकर्मा भगवान के जीवन चरित्र से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता राष्ट्रहित में त्याग तपस्या एवं बलिदान की अप्रतिम सीख लेते हैं तथा भारत सरकार से विश्वकर्मा जयन्ती दिवस 17 सितम्बर को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने का प्रमुख माँग करते हैं। यह कार्यक्रम भी लगभग सभी सक्रिय इकाईयों में प्रतिवर्ष सम्पन्न होता है।

3. **सर्वपंथ समादर मंच**—भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय में सर्वपंथ समादर मंच की पट्टिका लगी है। सभी कार्यालयों में यह पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाने का निर्णय है। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च

को इस मंच के झंडे तले गणेश शंकर विद्यार्थी शहादत दिवस मनाया जाता है। यह भी भारतीय मजदूर संघ का एक दैनन्दिन कार्यक्रम है। इस दिन विभिन्न पंथों से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता निर्धारित स्थान पर उपस्थित होते हैं जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह कार्यक्रम भी लगभग सक्रिय जिला केन्द्रों पर प्रतिवर्ष अवश्य सम्पन्न होता है।

4. **बाबू गेनू बलिदान दिवस**—यह कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष 12 दिसम्बर को स्वदेशी जागरण मंच के झंडे तले मनाया जाता है तथा बाबू गेनू के जीवन चरित्र से सीख लेकर स्वदेशी अपनाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं।

समन्वय बैठक—भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख आनुसांगिक संगठनों की समन्वय बैठकों में भाग लेते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रहित, समाजहित के अपेक्षित समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ होती हैं तथा अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं।

राज्य स्तरीय श्रम समितियाँ—इस कालावधि में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति एवं कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति की बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व रहा। इस अवधि में बीड़ी श्रमिक कल्याण परिषद् की भी बैठक हुई। बिहार सरकार के द्वारा कई समितियों का पुनर्गठन भी लम्बे समय से नहीं हुआ है तथा बैठकें भी नहीं हुई हैं।

श्रमिक शिक्षा वर्ग—केन्द्रीय/क्षेत्रीय श्रमिक परिषद—केन्द्रीय श्रमिक परिषद, नागपुर द्वारा स्वीकृत 3 पाँच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम (ग्राण्डस-इन-एड) प्रदेश के तीन स्थानों यथा, बिहार शरीफ, मोतिहारी एवं खगड़िया में विगत मार्च, 2002 में सम्पन्न हुए जिसमें प्रत्येक स्थान पर 40-40 कार्यकर्त्ताओं का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हुआ।

इसी प्रकार विचारणीय कालावधि में क्षेत्रीय श्रमिक शिक्षा निदेशालय मुजफ्फरपुर के द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों द्वारा भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में पटना में असंगठित क्षेत्र (मलीन वस्ती) श्रमिकों के दो दिवसीय दो कार्यक्रम बिहार शरीफ में असंगठित क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं के दो दिवसीय एक कार्यक्रम तथा मोतिहारी में भी असंगठित क्षेत्र श्रमिकों का दो दिवसीय एक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान—यह संस्थान विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास हेतु कार्यक्रम चलाते रहता है, जिसका पूर्ण व्यय भी संस्थान द्वारा वहन किया जाता है। विचारणीय कालखण्ड के अनेक कार्यक्रम सम्पन्न हुए तथा अपने असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ—रेलवे, डाक, दूरसंचार, प्रतिरक्षा तथा राज्य कर्मचारी संगठनों के प्रान्तीय स्तर संगठनों का समन्वय समिति गठित है। इस परिसंघ के माध्यम से जिला स्तरीय समितियों का गठन एवं केन्द्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश में सम्पन्न करने हेतु सक्रियता की अत्यंत अपेक्षा है।

नयी लेखा पद्धति वित्तीय अनुशासन—प्रदेश द्वारा भारतीय मजदूर संघ की विहित नई लेखा पद्धति द्वारा लेखा अभिलेखों को लिखा जा रहा है। इस अवधि में प्रदेश लेखा को एक बार केन्द्रीय अधिकारी श्री पी. टी. राव जी द्वारा जाँच की गयी तथा उपयुक्त मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। यूनियनों की लेखा पद्धति में भी विहित पद्धति लागू करने की अपेक्षा है।

औद्योगिक केन्द्र गतिविधि—**विद्युत**—बिहार प्रदेश विद्युत श्रमिक संघ की इस अवधि में आरा, जहानाबाद एवं गया में शाखाएँ गठित हुईं। जुलाई, 2002 में राज्य विद्युत बोर्ड मुख्यालय पर लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय सामूहिक धरना एवं उपवास किया गया। वेतन पुनरीक्षण एवं अन्यान्य लंबित मांगों पर समन्वय समिति / संयुक्त मोर्चा आदि में संघ की अच्छी भूमिका रही। हाल के विद्युतकर्मियों ने महत्वपूर्ण लम्बित मांगों पर गठित संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रबंधन का घेराव आदि आंदोलन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए थे। अपने कार्यकर्त्ताओं के सार्थक प्रयासों से सम्मानजनक स्थानांतरण वापसी आदेश जारी हुए।

इंजीनियरिंग—गया में दया इंजीनियरिंग में अपनी सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। गया से दो कार्यकर्त्ता अखिल भारतीय कार्यसमिति की वाराणसी बैठक में भाग लिये। कार्य बढ़ाने के लिये चिन्ता हो रही है। इस अवधि में कई कार्यक्रम भी हुए।

डाक एवं दूरसंचार—डाक विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, आर. एम. एस. एवं ग्रामीण डाक प्रभागों के अतिरिक्त डाक लेखा में अपना अच्छा काम है। सभी सर्किल यूनियनें अपना वार्षिक सम्मेलन संपन्न कराये। प्रशासनिक / सिविल विंग में कार्य खड़ा करने की आवश्यकता है। कार्यरत यूनियनों का प्रबंधन के साथ उपयोगी वार्ताएँ होती हैं। डाक विभाग कर्मियों का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग पटना में सम्पन्न हुआ था। वहीं दूरसंचार विभाग का 01.10.2000 से निगमीकरण कर दिया गया तथा गठित यूनियनों के बीच मान्यता हेतु चुनाव दिनांक 25.09.02 को सम्पन्न हुए जिसमें कार्यरत अपनी यूनियन वी.एस.एन.एल. मजदूर संघ को मान्यता नहीं मिल सकी, यद्यपि कि प्रतिस्पर्द्धी यूनियनों में किसी को भी 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं प्राप्त हुए। इस उद्योग में अपना कार्य विस्तार हेतु कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। कार्यरत यूनियन द्वारा दिनांक 27.11.02 को अपनी बहुसूत्री मांगों पर सर्किल मुख्यालय पर एकदिवसीय धरना दिया गया।

परिवहन—उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है। कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़े हैं। प्रयोग होते हैं पर सफलता नहीं मिलती। सरकार एवं प्रबंधन का रूख भी ठीक नहीं है। अपना प्रमुख कार्यकर्ता एवं यूनियन का महामंत्री प्रबंधन के द्वारा प्रतिद्वंदी यूनियनों की सह यर का शिकार हुआ है। एक कठिन संघर्ष चल रहा है।

बैंक—धीरे धीरे पर लगातार इस क्षेत्र में अपना कार्य प्रभावी हो रहा है विचारधीन अवधि में प्रदेश महासंघ बिहार प्रदेश बैंक वर्कस ऑरगनाईजेशन का पटना में सम्मेलन सम्पन्न हुआ। 26-10-2002 को

एन. ओ. बी. डब्ल्यू. के महामंत्री श्री इन्दूरकर जी का बिहार प्रवास हुआ तथा कार्यकर्त्ता बैठक हुई। विजया बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंकों में अपना कार्य है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों में अपना अच्छा एवं प्रभावी कार्य हैं। ग्रामीण बैंक के कार्यकर्त्ताओं द्वारा केन्द्र द्वारा आहूत तथा स्थानीय समस्यावों पर संघर्षात्मक कार्यक्रम भी होते हैं। ग्रामीण बैंक की अपनी सभी यूनियनों का वार्षिक सम्मेलन अनिवार्य रूप से सम्पन्न होता है।

बीमा—कार्य विस्तार का सिलसिला जारी है। कार्यकर्त्ता सक्रिय है तथा कार्य विस्तार की योजना करते हैं। 22/23 अक्तूबर 2002 को एन. ओ. आई. डब्ल्यू. की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में हुई तथा 23-10-2002 को अपराह्न पटना डिविजनल कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ जिसे संघ के अखिल भारतीय महामंत्री, संगठन मंत्री तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने संबोधित किया। पटना डिविजनल प्रबंधन द्वारा अपन यूनियन के कार्यकर्त्तावों के साथ दण्डात्मक नीति अपनाकर अखिल भारतीय मंत्री तथा स्थानीय प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री वी. के. सिन्हा का स्थानांतरण किया गया एवं एक झुठे अभियोग पत्र जारी किया गया जिसके विरूध सभी इकाईयों द्वारा केन्द्रीय आहवाहन पर धरना दिया गय। अपने कार्यकर्त्ता संघर्षशील है। सफलता प्राप्त होगी।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान—विशेष रूप से अपना कार्य एन. टी. पी. सी. कहगाँव तथा बरौनी रिफाईनरी में है। बरौनी फर्टीलाईजर के हाल ही में बन्दहोने के कारण कार्य सिमिल है। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर इस क्षेत्र में अत्यन्त अफरा-तफरी है। एन. टी. पी. सी. कहलगाँव में अपने कार्यकत्ताओं द्वारा विभिन्न प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधित्व है तथा वाताएं होती है।

रेलवे—पूर्वी मध्य रेलवे जोन में अपनी यूनियन का निबंधन हो चुका है। मान्यता हेतु प्रयास चल रहे हैं। विभाग द्वारा मध्यन्यत हेतु आदेश जारी हो चुका है, पर कोर्ट केश के कारण अभी तक स्थगित है। कार्य बढाने हेतु अनेक प्रयास जारी है।

प्रतिरक्षा—प्रदेश में दो यूनियने दानापुर में कार्यरत हैं। दोनों यूनियनों के कार्यकर्त्ता सक्रिय है। अपनी मान्यता भी प्राप्त है।

अँगन-वाड़ी—अपना कार्य दरभंगा, समस्तीपूर एवं फतुहाँ में खड़ा हो चुका है। इस उद्योग में कार्य बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं।

चीनी उद्योग—सरकारी चीनी मिलें बंद होने के कारण स्थिति दयनीय है। मोतिहारी नरकटियागंज तथा मझौलिया, गोपालगंज आदि में अपना काम है। कुछ सक्रिय कार्यकर्त्ता कार्य विस्तार हेतु प्रयत्नशील हैं। अखिल भारतीय महामंत्री श्री रामदौर सिंह जी का दौरा होता है।

सीमेंट—सिर्फ बनजारी सीमेंट में अपने कुछ कार्यकर्त्ता हैं। लम्बित कोर्ट केश के कारण वहाँ कार्य रूक गया है।

छोटे उद्योग एवं असंगठित क्षेत्र—भागलपुर जिले में भारतीय कोल डम्प मजदूर संघ ने बोनस तथा लेवलिंग मजदूरों की छँटनी का मामला उठाकर 6 अक्टूबर, 2002 से आंदोलन चलाया। लम्बे संघर्ष के बाद सफलता मिली, बोनस प्राप्त हुआ। छँटनी का मामला केन्द्रीय श्रम विभाग में लम्बित है। संविदा मजदूर संघ भी केन्द्रीय श्रम विभाग में अपने मामले दायर किये हैं। मुंगेर में सिगरेट तथा बन्दूक कारखानों में अपना काम प्रभावी है। दुकान कर्मचारी, ठीकेदार मजदूर संघ, कोल्ड स्टोरेज, बीड़ी, प्रेस, सिनेमा भवन निर्माण तथा टेम्पो/ट्रक चालक आदि में अपना कार्य है। कार्य विस्तार पर बल दिया जा रहा है। हाल ही में दिनांक 5.4.2003 को पटना में भवन एवं पथ निर्माण मजदूरों द्वारा संघ के झंडे तले एकदिवसीय धरना दिया गया तथा 18 सूत्री मांगों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ग्रामीण एवं कृषि मजदूरों में भी अपना कार्य पटना, मोतिहारी आदि में आरंभ हो चुका है। असंगठित क्षेत्र की तरफ उतरोत्तर ध्यान दिया जा रहा है। आशा है कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रभावी कार्य खड़ा हो जायेगा।

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ—महासंघ का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। पटना सचिवालय में शाखा का गठन हो चुका है। पटना में राज्य कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के कार्य से जुड़े हैं। अन्य जिलों में भी सभी विभागों में कार्य खड़ा करने का प्रयास जारी है। सरकारी प्रेस कर्मियों के बीच अपना कार्य पटना तथा गया में है।

आभार प्रदर्शन—विगत सवा दो वर्षों के कालखण्ड में कार्य संचालन में सहयोग हेतु अपने सभी सहयोगियों, कार्यकर्त्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट कर रहा हूँ। अपने केन्द्रीय अधिकारियों विशेषकर माननीय ओम प्रकाश अग्घी, मा० राम प्रकाश जी मिश्र एवं मा० वैजनाथ राय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शनों से हमें लाभान्वित किया। अपने सभी शुभचिन्तकों, जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त होता रहा उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

अन्त में, कार्य संचालन करते समय किन्हीं भी श्रेष्ठ जनों तथा कार्यकर्त्ताओं को जाने-अनजाने ठेस पहुँची हो तो उनके प्रति क्षमा याचना करते हुए सभी प्रतिनिधि भाई बंधुओं से प्रस्तुत लघु प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ।

भारत माता की जय !!!

राजदेव तिवारी
प्रदेश महामंत्री

मुद्रक : **लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस**, डी० एन० दास लेन, पटना-4, दूरभाष : 2674928